E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2023; 5(2): 159-162
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 21-08-2023
Accepted: 25-09-2023

विकास कुमार मीना
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, काशी हिन्दू विश्वविधालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत

सचिन तिवारी
राजनीति विज्ञान विभाग, काशी हिन्दू विश्वविधालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
विकास कुमार मीना
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, काशी हिन्दू विश्वविधालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत

दक्षिण एशिया की बदलती राजनीति में भारत और नेपाल के संबंध: एक सामरिक महत्व

विकास कुमार मीना, सचिन तिवारी

DOI: https://doi.org/10.33545/26646021.2023.v5.i2c.276

सारांश
भारत के उत्तर में स्थित नेपाल एक भू–आबद्ध राष्ट्र है। जिसका अपना एक समृद्ध और सुसज्जित इतिहास है। भारत के साथ इसके सदियों पुराने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, व्यापारिक तथा धार्मिक संबंधों ने इसके विकास का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसके मूल में समान धर्म- संस्कृति, सौहार्द, प्रगति और उन्नति है। भारत- नेपाल संबंधों की रूपरेखा सदियों पुराने हिन्दू-बौद्ध धर्म के विकास तथा व्यापारिक मार्गों की उन्नति से प्रदर्शित होती है जो कालांतर में आर्थिक, प्रौधोगिक, रणनीतिक, भौगोलिक तथा मानवीय है परंतु बदलती भू- राजनीतिक परिवेश में दोनों राष्ट्रों ने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति तथा प्रगति हेतु विपरीत साधनों का इस्तेमाल किया है जिससे भारत- नेपाल संबंधों में खटास की अनुभूति हुई है। मुख्य कारणों में नेपाल का चीन की तरफ झुकाव, मधेशी संकट, भारतीय क्षेत्रों को नेपाली मानचित्र में प्रदर्शित करना, देह व्यापार और मानव तस्करी आदि सम्मिलित है परंतु विभिन्न विवादों के उपरांत भी दोनों राष्ट्रों के मध्य संबंध अत्यंत सौहार्दपूर्ण हैं तथा भारत द्वारा नेपाल के विकास में असीमित संसाधनों और धन- सेवा की आपूर्ति निर्बाध रूप से दी जा रही है तथा सरकारी स्तर पर विभिन्न संधियों और सम्मेलनों द्वारा इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति भी होती है। भारत नेपाल के संबंधों में ऐतिहासिक विकास के लक्षण विद्यान है जो सन 2014 के बाद और अधिक प्रगाढ़ हुए हैं तथा मोदी सरकार की पड़ोसी प्रथम की नीति ने नेपाल के साथ भारत के रणनीतिक और सामरिक संबंधों को और बढ़ा दिया है जिससे रोटी- बेटी का प्रचलित संबंध विद्यमान रह सके। इस प्रकार भारत और नेपाल के मध्य एक सौहार्दपूर्ण और मित्रवत संबंध का होना भौगोलिक, सामरिक तथा रणनीतिक लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है जिससे दोनों पड़ोसी राष्ट्रों का तीव्र गति से विकास हो सके।

कूटशब्द : भौगोलिक, मधेशी, रणनीतिक, सौहार्दपूर्ण, सामरिक, भारत-नेपाल।

प्रस्तावना
भारत की विदेश नीति में नेपाल का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछली कई सदियों से घनिष्ट रहे है। वर्ष 1950 में भारत और नेपाल के बीच हुई मैत्री संधि तथा खुली सीमा ने दोनों देशों के संबंध को विशिष्ट बनाया। शांति और मैत्री संधि ने नेपाली नागरिकों को सीमा पार मुक्त आवाजाही और भारत में कानूनी रोजगार के अवसरों की गारंटी दी। लेकिन अब, इसे एक असमान रिश्ते और भारतीयों द्वारा थोपी गई चीज़ के संकेत के रूप में देखा जाता है।

1990 के दशक के मध्य से, संयुक्त वक्तव्यों में कभी-कभी, लेकिन हमेशा नहीं, संशोधन और अधतन करने के विचार के बारे में बात की गई है। भारत ने प्रत्येक कालखंड में नेपाल में लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना करने में मदद की, नेपाल जैसे भू- आबद्ध राष्ट्र और गरीबी एवं कमजोर अर्थव्यवस्था में सहायता करने के लिए उसे तीसरे देशों से व्यापार करने में आर्थिक सहायता प्रदान की ओर वहां विकासशील परियोजनाओं को स्थापित करने में मदद की है।

यह शोध अध्ययन भारत और नेपाल के संबंधो का अध्ययन भारतीय दृष्टिकोण से वर्ष 2014 के बाद हुए विकास पर अध्ययन प्रस्तुत करेगा। वर्ष 2014 में भारत में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव होता है और NDA की सरकार केंद्र में सत्ता में आती है ओर श्री नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते है, विदेश नीति में गुजराल सिद्धांत का अनुसरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने "पड़ोस पहले की नीति" को प्रमुखता दी, इसी क्रम में उन्होंने दक्षिण एशिया के सबसे छोटे देश भूटान की पहली यात्रा की और दूसरी यात्रा नेपाल कि की। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की संसद को संबोधित किया ओर शस्त्र से शास्त्रों की तरफ जाने की बात की, इससे यह पुष्टि होती है की भारत हमेशा नेपाल में लोकतांत्रिक संस्थाओ के पक्ष में मजबूती से खड़ा है। दोनों देशो के बीच आर्थिक संबंधो को देखा जाए तो भारत और नेपाल के मध्य पिछले एक दशक में व्यापार बढ़ा है ओर साथ ही विकासशील परियोजनाओं में वृद्धि हुई है जिसमें अरुण-3 पन बिजली परियोजना, काठमांडू से दिल्ली रेल परियोजना तथा नदियों के माध्यम से व्यापार करने की परियोजना प्रमुख है, भारत और नेपाल में हिन्दू समुदाय की बहुतायता होने के कारण धार्मिक कारक ने हमेशा दोनों में नजदीकी बनाये रखी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर और मुक्तिधाम मंदिर एवं जनकपुर की यात्रा इसमे उल्लेखनीय है, रामायण सर्किट जैसी परियोजनाओं को लाने से धार्मिक पर्यटन में भी बढ़ोतरी होगी। भारत के अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर जैसे धार्मिक नगरों से नेपाल के पुराने संबंध रहे है। भारत और नेपाल के मैत्रीपूर्ण संबंध दोनों देशों के साझा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों और जनता के करीबी संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित है। भारत-नेपाल के मध्य "शांति एवं मैत्री संधि" (1950) से दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों की शुरुआत हुई। इस संधि के परिणामस्वरुप नेपाल के लोगों को भारत में भारतीय नागरिकों के समान सुविधाएं और अवसर प्रदान किए गए। दोनों देशों के राजनेताओं व अधिकारियों के बीच नियमित रुप से उच्च स्तरीय बातचीत होती रहती है। भारत-नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के संबंधों की विशिष्टता है, जिससे दोनों देशों के लोगों को आवागमन में सुगमता रहती है। दोनों देश 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करते हैं, जिसमें अच्छी बात है कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच कोई बड़ा सीमा विवाद नहीं है। लगभग 98% सीमा की पहचान और उसके नक्शे पर सहमति बन चुकी है। लेकिन वर्तमान में नेपाल पर चीन के बढ़ते प्रभाव के चलते भारत- नेपाल संबंधों को और अधिक पर मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके लिए भारत को नेपाल के प्रति अपनी नीति दूरदर्शी बनानी होगी। नेपाल में चीन के बढ़ते दखल के बाद पिछले कुछ समय से भारत-नेपाल के बीच संबंधों में पहले जैसी गर्मजोशी देखने को नहीं मिल रही है। चीन ने इसका पूरा-पूरा लाभ उठाते हुए नेपाल में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। सन् 2015 में जब नेपाल की तराई में बसे मधेसी समुदाय ने अपनी कुछ मांगो को न सुने जाने के कारण भारत-नेपाल सीमा पर कई दिनों तक आवाजाही को अवरुद्ध कर दिया था, तब नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने भारत-नेपाल की सीमा के कुछ महत्वपूर्ण रास्तों की नाकाबंदी करने का आरोप लगाते हुए इसे आर्थिक नाकाबंदी कहा था। इसके बाद ही नेपाल का झुकाव चीन की तरफ बढ़ने लगा था। इन सबके बावजूद भारत-नेपाल के साथ संबंध मजबूत बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। भारत की सबका साथ सबका विकास की विचारधारा समावेशी विकास और समृद्धि की एक साझा संकल्पना हेतु पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों के लिए एक दिशा-निर्देशक संरचना की तरह काम करती है। उधर नेपाल में राजनीतिक परिवर्तन के बाद वहां की सरकार ने 'समृद्ध नेपाल और सुखी नेपाल' के मूल मंत्र के आधार पर आर्थिक बदलाव को प्राथमिकता दी है। के पी शर्मा ओली 15 फरवरी 2018 को नेपाल के प्रधानमंत्री बने, इसके बाद भारत नेपाल के बीच कई आपसी यात्राएं और कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके माध्यम से दोनों देशों के मध्य सहयोग, कनेक्टिविटी, आपसी विश्वास और लोगों के मध्य आपसी संपर्क को बढ़ाने में काफी मदद मिली। मई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की चौथी यात्रा की और अपनी यात्रा को प्रधान तीर्थयात्री का नाम दिया न कि प्रधानमंत्री यात्रा। नरेंद्र मोदी भारत-नेपाल संबंधों को पुनः स्थापित करने के लिए दोनों देशों की समानता तथा परस्पर विश्वास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा (2022) ने नेपाल को सबसे अच्छे दोस्त के रूप में देखे जाने के लिए हर

संभव प्रयास किया - एक सामान्य व्यक्ति, एक तीर्थयात्री, जरूरतमंद नेपाली के अभिभावक, और एक बड़े देश के प्रधान मंत्री से कम। जब तक उन्होंने नेपाल छोड़ा, तब तक उन्होंने नेपालियों के दिल और दिमाग पर यह विचार गहराई से अंकित कर दिया था कि नेपाल को एक समृद्ध देश में बदलने की इच्छाशक्ति और क्षमता केवल उन्हीं में है। नेपाल की संप्रभुता के लिए भारत के सम्मान पर उनका बार-बार जोर देना, और यह संदेश कि अतीत के अवसर चूक गए और असफल वादों को "एक साथ मिलकर समृद्धि की हमारी भविष्य की यात्रा" में गति-अवरोधक के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, शायद उनका उद्देश्य भविष्य की ओर देखना था, न कि अतीत का राग अलापना।

सामाजिक दृष्टिकोण से देखे तो भारत और नेपाल की सीमा पर मधेश क्षेत्र के लोगों के संबंध भारत के सीमावर्ती राज्यों से हमेशा बने रहें, दोनों देशो के मध्य रोटी- बेटी का संबध यह दर्शाता है की सीमा के आर-पार विवाह भी होते रहें है ओर नेपाल के लोग रोजगार हेतु भारत आते भी रहें है। भारत और नेपाल समृद्ध हिंदू धर्म और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं । इसे जारी रखने के लिए, दोनों सरकारों ने इस साझा सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया है। भारत और नेपाल ने जनकपुर-अजोध्या, काठमांडू-वाराणसी, लुंबिनी-बोधगया को जोड़ने के लिए सिस्टर-सिटी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

व्यपारिक दृष्टिकोण से देखे तो भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना हुआ है। वित्त वर्ष 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार कर गया है। पिछले 10 वर्षों में नेपाल से भारत का निर्यात 8 गुना से अधिक बढ़ गया है जबकि नेपाल से निर्यात लगभग दोगुना हो गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में यह भारत के निर्यात का 2.34% था। दरअसल भारत से होने वाला निर्यात नेपाल की जीडीपी का लगभग 22% है। भारतीय कंपनियां नेपाल में सबसे बड़े निवेशकों में से हैं, जिनका नेपाल में कुल एफडीआई स्टॉक में 33% से अधिक हिस्सा है, जिसका मूल्य लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत और नेपाल ने नवंबर 2011 में दोहरे कराधान बचाव समझौते (डीटीएए) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। द्विपक्षीय प्रेषण प्रवाह लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (नेपाल से भारत) और 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (भारत से नेपाल) होने का अनुमान है।

भारत और नेपाल के मध्य पिछले कुछ दशकों से चीन भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। नेपाल, भारत और चीन के मध्य बफर स्टेट होने के कारण भारत के लिए सामरिक दृष्टि से सदैव महत्वपूर्ण रहा है। दोनों देशों में पुराने सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंध हैं और यहां तक कि नेपाल एवं भारत के लोगों को एक दूसरे के देश में यात्रा हेतु पासपोर्ट वीजा इत्यादि की भी आवश्यकता नहीं होती है। भारत ने प्रशासनिक एवं सैन्य पदों पर नेपाल के नागरिकों के लिए नौकरी का अवसर प्रदान किया हुआ है। इससे यह सुस्पष्ट है कि इन दोनों देशों के बीच आपसी संबंध कितना गहरा और महत्वपूर्ण है। जब भी नेपाल या भारत में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव दोनों देशों पर पड़ता है। जब भी कभी भारत और नेपाल में रिश्तों में तलखी आई है तब चीन ने अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की है, चीन की विस्तारवादी नीति और वर्तमान में उसकी "वन बेल्ट वन रोड परियोजना" जिसके द्वारा वह नेपाल को अपने प्रभाव में लेने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। चीन तिब्बत को नेपाल की राजधानी काठमांडू से जोड़ने वाली 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ट्रांस-हिमालयी रेलवे भी विकसित कर रहा है। चीन और नेपाल ने ट्रांस हिमालयन मल्टीडायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क के तहत तिब्बत और काठमांडू को जोड़ने वाली एक ऑल वेदर रोड के निर्माण के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

इस अध्ययन में भारत और नेपाल के बीच संबंधो में आई समस्याओं और अडचनों का भी अध्ययन किया गया हैं, साल 2015 में नेपाल द्वारा नया संविधान लाने के बाद रिश्तों में एक खटास देखी गई, इस नए सविधान का भारत ने स्वागत नही किया ओर कुछ संशोधन की बात कही क्योंकि इस संविधान द्वारा भारत नेपाल सीमा पर रहने वाले मधेशी लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है इसके बाद भारत और नेपाल की सीमा पर नाकेबंदी लगा दी गई जिससे की नेपाल में जनापूर्ति और रोजमर्रा के सामान जाना बंद हो गये जिससे नेपाल की जनता में भारत के प्रति रोष और अविश्वाश बढ़ने लगा इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चार ओर नेपाल की यात्राएं की और संबंधो को सुधारने का प्रयास किया। वर्ष 2017 में नेपाल में संसदीय चुनाव हुए जहाँ नेपाल में वामपंथी दलों ने नेपाली राष्ट्रवाद और भारत विरोधी बयानों के जरिये सत्ता हासिल करने की कोशिश की गई। अभी हाल ही में चीन के प्रभाव के अतिरिक्त अमेरिका भी नेपाल में अपना वर्चस्व बढ़ता हुआ दिख रहा हा जोकि भारत के लिए एक चुनौती बन सकता है।

निष्कर्ष

भूगोल और पड़ोस नहीं बदल सकते,वे एक वास्तविकता का निर्माण करते हैं जिसके साथ हमें जीना

और काम करना चाहिए। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि राष्ट्रीय राजधानियों के बीच राजनीतिक संबंध अलग-अलग हैं और जो महत्वपूर्ण है वह लोगों के बीच संबंधों की मजबूत नींव है। जब 1950 और 1960 के दशक में नेपाल भारत-बंद था, दुनिया के लिए खुल रहा था, तब राजनीति उतनी ही जटिल थी जितनी अब है, लेकिन लोगों से लोगों के जुड़ाव ने रिश्ते को आगे बढ़ाया। सीमा पर मौजूद लोगों को बातचीत के केंद्र में होना चाहिए, जैसे कि सीमा आर्थिक क्षेत्र जैसे नए मुद्दे। बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल (बीबीआईएन) का नया उप-क्षेत्रीय ब्लॉक, जिसे "पूर्वी दक्षिण एशिया" के रूप में संदर्भित किया जाता है, को पर्यटन, व्यापार, परिवहन, ऊर्जा और निवेश के आसपास क्षेत्रीय सहयोग सुनिश्चित करने के लिए मूलभूत संरचना होनी चाहिए। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने संबंध रहे है लेकिन संबंधो में उतार आने के कारणों को सुलझाने के लिए सर्वप्रथम भारत को नेपाल के साथ एक संप्रभु राष्ट्र और सामान दर्जे वाले राष्ट्र के रूप में व्यवहार करना होगा जिससे की वहाँ भारत विरोधी भावनाएं नियंत्रित होगी, नेपाल में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भी भारत को धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधो के साथ–साथ आर्थिक संबंधो को ओर मजबूत करना होगा।भारत को नेपाल को पूरी तरह से सुरक्षा के चश्मे से देखना बंद कर देना चाहिए, और द्विपक्षीय संबंधों को केवल लेन-देन और चीन के साथ शून्य-राशि के खेल के हिस्से के रूप में देखना चाहिए।भारत को दोनों देशों के लाभ के लिए बहुआयामी संबंधों की दिशा में काम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारत को सीमा पार जल विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तत्वावधान में नेपाल के साथ सीमा विवाद को हल करने के लिए कूटनीतिक रूप से बातचीत करनी चाहिए। ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद समाधान को इसके लिए एक मॉडल के रूप में काम करना चाहिए।भारत को नेपाल के आंतरिक मामलों से दूर रहने की नीति अपनानी चाहिए, साथ ही मित्रता की भावना से भारत को अधिक समावेशी लोकतंत्र की ओर राष्ट्र का मार्गदर्शन करना चाहिए।

संदर्भ

1. यादव सिंह भूपेंद्र , भारत नेपाल संबंध 2022
2. रंजीत रे , काठमांडू डिलेमा , रीसेटिंग इंडिया नेपाल टाइस , 2022
3. Adhikari Monalisa “Politics and Perceptions of India Aid to Nepal Strategic Analysis 2014”
4. बघेल वी. एस. भारत नेपाल संबंध में चीन की भूमिका क्राफ्ट पब्लिशर्स , 2023
5. Leo E Rose, John T Schloz. Nepal: Profile of Himalayan kingdom
6. Vani TR, Gupta D. India and Nepal relations during Narendra Modi regime; c2016.
7. Bahadur, Kalim, Lama, Mahendra P. ed. New Perspectives on India-Nepal Relations New Delhi, Har Anand; c1995.
8. Das RK. Nepal and its Neighbours: Quest for status of a Landlocked State, Varanasi; Konark; c1986.
9. Dharamdasani MD. Democratic Nepal", Varanasi: Shalimar; c1992.
10. Dharamdasani MD. Indian Diplomacy in Nepal", Jaipur: Aaiekh; c1976.
11. Dharamdasani MD. Ed. India and Nepal - Big Power Small Power Relations in South Asia. New Delhi South Asian Publisher; c2001.
12. Muni SD. Regional Co-operation in South Asia; c2001.
13. Muni SD. Foreign Polocy of Nepal, New Delhi; National; c1973.
14. Muni SD. India and Nepal: A Changing Relationship, New Delhi: Konark; c1992.
15. Muni SD. Understanding South Asia New Delhi. South Asian Pub.
16. Bhattarai KD. Resetting India-Nepal Relations, The Diplomat; c2018 Apr. Available At: https://thediplomat.com/2018/04/resetting-india-nepal-rela-tions/
17. Pant, Harsh V. Why India needs to Safeguard her ties with Nepal, Observer Research Foundation; c2018 Jun 27. Available At https://www.orfonline.org/research/41945-why-indianeeds-to-safeguard-its-tieswith-nepal?
18. Panda, Baijayanti, India's Foreign Policy: Gentrify Relations with Neighbours, The Economic Times; c2018 Jul 13.